nt>

Title: Need to ensure reservation to Schedule Tribes in Government services and various technical training institutes and corporations of Delhi Government.

MR. SPEAKER: There are names of 48 hon. Members in the list. Please tell me how can I equate 48 with one? Everyone will want to be the first speaker.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरी तथा दिल्ली के अंदर शैक्षणिक संस्थाओं और कार्पोरेशन में जो आरक्षण साढ़े सात प्रतिशत मिलता था, वह बंद कर दिया। महोदय, यह पूरे देश का सवाल है। पिछली बार जब श्री अटल जी की सरकार थी, 1998 में इसे बैन कर दिया गया था। सारे देश भर के आदिवासी और पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने प्रधानमंत्री जी से मिल कर इसे नियमित करने की प्रार्थना की। पिछली पांच जुलाई को यूपीए की सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार और यूपीए की सरकार ने टोटल आरक्षण बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के आदिवासी और दिल्ली में अनेक ऐसे क्षेत्रों से यहां लोग आते हैं, परन्तु उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला नहीं मिलता। आदिवासियों के नाम पर रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी वेकेंसियां निकलीं, परन्तु उन्हें रोक दिया गया और सारे का सारा आरक्षण बंद कर दिया।

महोदय, यह सारे देश के आदिवासियों का सवाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से 1955 से निरंतर अभी तक दिल्ली के अंदर आदिवासियों को आरक्षण मिलता रहा है, उसे बंद क्यों कर दिया? सरकार को बताना चाहिए कि इसका कौन सा कारण है? हमारे देश के आदिवासियों के लिए यह बड़ा गंभीर सवाल पैदा हो गया है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में कार्यवाही करे । आदिवासियों को मिलने वाली जो 7.5 परसेंट की सुविधा है, यह निरन्तर हमारे आदिवासियों को दिल्ली के अन्दर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था और संरक्षण मैं चाहता हूं।